@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

किसानों को अन्नदाता के रूप में देखती है हमारी सरकार: नरेन्द्र मोदी

वर्ष-16, अंक-01 01-15 जनवरी, 2021 (पाक्षिक) ₹20

'सोनार बांग्ला' बनाने हेतु प्रतिबद्ध भाजपा

रामकृष्ण मिशन आश्रम, सरिसा (पश्चिम बंगाल) में प्रार्थना करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

हस्टिंग कार्यालय (कोलकाता) से प्रदेश भाजपा चुनाव कार्यालय और 9 जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

डायमंड हार्बर (कोलकाता) में मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) के रवीन्द्र भवन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में महान शहीद श्री खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **ममता सरकार को उखाड़ फेंक कमल की सरकार बनानी है: जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती और पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 120 दिनों के राष्ट्रव्यापी विस्तृत प्रवास के तहत 9 एवं 10 दिसंबर, 2020 को पश्चिम बंगाल...

09 **हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे: अमित शाह**
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 19 दिसंबर, 2020...

24 **नई संसद 'आत्मनिर्भर भारत' का बनेगी गवाह: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नया भवन 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि का...

28 **किसानों को अन्नदाता के रूप में देखती है हमारी सरकार: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम मध्य प्रदेश में हुए किसान सम्मेलन को संबोधित किया...

32 **लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए अधिक उपयुक्त...**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 दिसंबर को भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित...

वैचारिकी

अपनी विचारधारा सहयोग पर आधारित / दीनदयाल उपाध्याय 15

श्रद्धांजलि

नहीं रहे विचारक माधव गोविंद वैद्य 17

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन 17

लेख

सभी दलों के लोग अटलजी को अपना मानते थे / प्रभात झा 22

अन्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को दी मंजूरी 12

बैंक टू बैंक लोन के तौर पर राज्यों को जारी की गई 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं किस्त 13

27 राज्यों ने 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना' का उठाया लाभ 14

स्थानीय निकाय चुनावों में खिला कमल 18

'राजनीति इंतजार कर सकती है, देश का विकास नहीं' 26

भारत-बांग्लादेश के बीच हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा समेत हुए सात समझौते 27

कृषि सुधारों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है: नरेंद्र सिंह तोमर 30

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिला अमेरिका का 'लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है– एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर। किसान पहले चाहकर भी अपनी फसल मंडी के अलावा कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून के मुताबिक किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, यह उसकी मर्जी होगी।

जगत प्रकाश नड्डा

किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती है। ये कांग्रेस की मौक़ापरस्त सोच, कम जानकारी व बार-बार बात से पलटने का प्रमाण है।

अमित शाह

मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेन्द्र मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह

नए कृषि क़ानूनों में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। मोदीजी के नेतृत्व की सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, जो किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाला हो।

बी. एल. संतोष

'सबका साथ, सबका विकास' की अपनी नीति के अनुरूप मोदी सरकार ने 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों के लाभ हेतु 5 वर्ष की अवधि में 59,000 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। समावेशी विकास की दिशा में बहुत बड़ा कदम। धन्यवाद, थावरचंद गेहलोत।

नितिन गडकरी

ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से हम जल्द ही गाय के गोबर से बना 'वैदिक पेन्ट' लॉन्च करने वाले हैं। डिस्टेंपर और इमल्शन में आने वाला यह पेंट इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल होगा और केवल चार घंटे में सुखेगा। इससे पशुधन रखने वाले किसानों को साल में 55 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी।

भाजपा को मिला देशव्यापी जन-समर्थन

जम्मू-कश्मीर जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों में भाजपा की भारी विजय से इस क्षेत्र के राजनैतिक इतिहास का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। डीडीसी चुनावों का सफलतापूर्वक संपन्न होना, भारी संख्या में मतदान एवं जिस प्रकार से पूरी चुनाव प्रक्रिया में जनता की भागीदारी रही, उससे जनता का राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र एवं विकास की राजनीति में अदम्य विश्वास प्रमाणित हुआ है। हालांकि, गुपकार गठबंधन के घटक दल अब भी आत्ममंथन करने से इंकार कर सकते हैं। अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रत्याशियों की जीत से जम्मू-कश्मीर में ऐसे राजनैतिक नेतृत्व के अभ्युदय का संकेत मिलता है, जो जनाकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर की जनता परिवारवाद की प्रतिगामी राजनीति, भ्रष्टाचार एवं अलगाववाद को नकार कर आने वाले दिनों में विकास एवं राष्ट्रीय एकता व अखंडता के युग का आलिंगन करना चाहती है। डीडीसी चुनावों से न केवल लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, बल्कि इससे इस क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति जन-जन की आस्था भी प्रदर्शित हुई है।

पूरे देश में जनता भाजपा को विजय का आशीर्वाद दे रही है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को व्यापक समर्थन भी दे रही है। एक ओर जहां बिहार विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता द्वारा राजग को चौथी बार स्पष्ट बहुमत का आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर साथ में संपन्न हुए उपचुनावों में भी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना एवं मणिपुर समेत पूरे देश में जनता का भरपूर आशीर्वाद भाजपा को मिला है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली है। हैदराबाद महानगरपालिका चुनावों में भी देश के सभी राजनैतिक पंडितों को अचंभित करते हुए भाजपा ने अपनी सीट कई गुना अधिक बढ़ा ली है। चाहे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का चुनाव हो या अरुणाचल प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव या फिर लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव हर जगह 'कमल' ही 'कमल' खिल रहा है। राजस्थान स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने ग्रामीण एवं शहरी, दोनों में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। यहां तक कि केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की सीटों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आज जबकि जनता भाजपा को पंचायत से लेकर पार्लियामेंट के चुनावों में अपना भारी समर्थन दे रही है, यह स्पष्ट है कि भाजपा देशभर में जनाकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरी है।

आज जबकि भाजपा के लिए पूरे देश में जनसमर्थन हर दिन व्यापक रूप से बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों की जमीन पैरों तले खिसक चुकी है।

आज जबकि भाजपा के लिए पूरे देश में जनसमर्थन हर दिन व्यापक रूप से बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों की जमीन पैरों तले खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर निंदनीय हमले से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की तृणमूल कांग्रेस सरकार काफी तिलमिलाई हुई है। अब जबकि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी बारी हार चुकी है, कांग्रेस स्वयं को हताशा में अपने विनाश की ओर धकेल रही है। हताशा एवं निराशा में कांग्रेस आज देश में विभाजनकारी तत्वों से मेलजोल कर 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के साथ खड़ी दिखती है तथा देश में विषवमन एवं कुप्रचार के माध्यम से भ्रम फैलाना चाहती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण उसके द्वारा देश में व्यापक परिवर्तन लाने वाला किसान हितैषी कृषक सुधार कानूनों का आधारहीन विरोध है। इन क्रांतिकारी सुधारों का समर्थन करने के स्थान पर यह किसानों के एक वर्ग में भ्रम फैलाकर देश में गतिरोध पैदा करना चाहती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं करिश्माई नेतृत्व में भारत आज एक नए उत्साह एवं उमंग से भरा हुआ है। अमेरिका द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार वास्तव में भारत की जनता का अभिनंदन है जो बार-बार श्री नरेन्द्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है। भाजपा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान को मिल रहा भारी जनसमर्थन आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। आज जब एकता, अखंडता एवं विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण से देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

ममता सरकार को उखाड़ फेंक कमल की सरकार बनानी है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती और पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 120 दिनों के राष्ट्रव्यापी विस्तृत प्रवास के तहत 9 एवं 10 दिसंबर, 2020 को पश्चिम बंगाल का दो दिवसीय प्रवास किया। विदित हो कि इस विस्तृत प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने इसी महीने 4 दिसंबर से उत्तराखंड से की थी।

अपने प्रवास के पहले दिन 9 दिसंबर, 2020 को हेस्टिंग्स, कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा के नए चुनाव कार्यालय और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के 9 जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल रॉय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश, लोकसभा सांसद सुश्री लॉकेट चटर्जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा, श्री अनुपम हाजरा सहित कई पार्टी पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भाजपा के प्रदेश चुनाव कार्यालय और 9 जिला भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज 9 जिला कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है, आगे चलकर 38 और जिला कार्यालय बनने हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए हमें दुःख भी होता है, शर्मसार भी होता हूं। जो बंगाल कभी अपनी संस्कृति, विराट हृदय और सोनार बांग्ला के लिए जाना जाता था, आज वहां हिंसा, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अपना-पराया और विकास के विरुद्ध काम करने का रास्ता टीएमसी सरकार ने अपना रखा है। पिछले कुछ वर्षों में 130 कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 100 से अधिक दिवंगत पार्टी कार्यकर्ताओं का तर्पण मैंने स्वयं किया है। पश्चिम बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या? टीएमसी सरकार इंसानियत के भी विरोध में है और इसने राजनीतिक असहिष्णुता की पराकाष्ठा पार कर ली है। मेरा यह मानना है कि जहां विचार की लड़ाई ख़त्म हो जाय, हिंसा की राजनीति शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि वहां राजनीतिक एक्टिविटी ख़त्म हो रही है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि वे इस कठिन परिस्थिति में भी डटे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2021 में ममता बनर्जी सरकार का सफाया तय है। हाल ही में हमारे विधायक श्री देवेन्द्र नाथ रॉय की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी हत्या को तृणमूल सरकार ने आत्महत्या सिद्ध करने की कोशिश की। इसी तरह

हमारे युवा कार्यकर्ता श्री मनीष शुक्ला की दिनदहाड़े ऑटोमेटिक गन से नृशंस हत्या कर दी गई और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। स्पष्ट है कि ये हमले स्टेट स्पोंसर्ड हैं और राजनीतिक हित साधने के लिए पुलिस का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि तृणमूल सरकार हमेशा नहीं रहने वाली, भाजपा का सरकार बनना निश्चित है।

तृणमूल सरकार की राजनीतिक असहिष्णुता का उदाहरण देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि अभी हाल ही में जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर श्री अम्बिकेश महापात्रा को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया, आरामबाग टीवी के एडिटर श्री शफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टीएमसी के करप्शन को उजागर किया था। इसी तरह आनंद बाजार पत्रिका के एडिटर श्री अनिर्बान चट्टोपाध्याय को ओवरनाइट हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने जनता के सामने सच्चाई रखी थी। जंगलमहल में हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए अपराधियों को जेल से निकाल कर टीएमसी, पार्टी का प्रवक्ता बना रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बीते 30 जुलाई और 01 अगस्त को ईद के कारण लॉकडाउन हटा लिया गया, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद ही 05 अगस्त को जबरन कर्फ्यू लगा दिया गया जिस दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हजारों साल से करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुसार भगवान् श्रीराम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं तो और क्या थी?

• पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार की दमनकारी नीति से ऊबकर अब परिवर्तन का मन बना चुकी है। कमल खिलने वाला है

श्री नड्डा ने कहा कि हमें सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ना है, एक विकसित पश्चिम बंगाल बनाना है। चाहे फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, ह्यूमन ट्रेफिकिंग का मामला हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो, आज पश्चिम बंगाल इस सब में सबसे आगे है। अब तो ममता सरकार ने क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आंकड़े देना भी बंद कर दिया है। न तो कोरोना के आंकड़े बताती है, न डेंगू के मामलों की जानकारी देती है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के गरीबों और किसानों का हक मारने का काम किया है। वह न तो आयुष्मान भारत योजना राज्य में लागू होने दे रही है और न ही किसान सम्मान निधि योजना का फायदा किसानों को लेने दे रही है। राज्य के 75 लाख किसान इसके लाभ से अब तक वंचित हैं।

दूसरे दिन का प्रवास

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा अपने 120 दिनों के राष्ट्रव्यापी प्रवास के तहत दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन साउथ 24 परगना जिला में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मलेन आयर डायमंड हार्बर में सामाजिक समूह सम्मलेन को संबोधित करते हुए प्रदेश की अराजकतावादी और असहिष्णु टीएमसी सरकार की सत्ता उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

श्री नड्डा ने कहा कि एम्फान तूफ़ान के समय प्रदेश की जनता की मदद के लिए केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 1 हजार करोड़ रुपये एडवांस दिए गए और 12 हजार करोड़ रुपये अलग से भेजने की व्यवस्था की गई थी लेकिन ममता जी ने भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक जो संलिप्तता दिखाई, उससे हाइकोर्ट तक को कहना पड़ा कि इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। इसलिए सीएजी से इसकी ऑडिट कराई जाए लेकिन ममता जी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ 67 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर देना तय किया था लेकिन ममता सरकार ने भय से इस योजना को लागू न करके प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को 4,500 करोड़ रुपये दिए गए, 3,000 करोड़ रुपये पहली किश्त में दिए गए लेकिन ममता सरकार ने इन पैसों को लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के समय देश की 80 करोड़ जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल प्रति परिवार के लिए भिजवाया था, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसमें भी भ्रष्टाचार किया और चावल की चोरी टीएमसी कार्यकर्त्ता के घर से पकड़ी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल पश्चिम बंगाल के किसानों के खाते में 6,000 रुपये पहुंचना था लेकिन ममता सरकार इसे होने नहीं दे रही। आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारी टीएमसी सरकार की छुट्टी करनी है और भाजपा की सरकार बनानी है, ताकि करीब 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केंद्र से पैसा प्रदेश सरकार को भेजती तो है लेकिन ममता सरकार के लोटे में छेद होने की वजह से सारा पैसा 'कट मनी' के तहत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। श्री नड्डा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को ममता सरकार के भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी है और कमल खिलाना है, ताकि केंद्र से भेजी गई धन-राशि का समुचित उपयोग प्रदेश की जनता के लिए हो सके।

श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार की दमनकारी नीति से ऊबकर अब परिवर्तन का मन बना चुकी है। मैं आश्वस्त हूं कि पश्चिम बंगाल में इस बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और डायमंड हार्बर में भी कमल खिलने वाला है। अतः मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप जनता के बीच जाएं, जनता तहे दिल से स्वागत के लिए आपका इंतज़ार कर रही है। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने किया हमला

पश्चिम बंगाल में अराजकता एवं असहिष्णुता कायम है। राज्य में लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। पिछले एक साल में भाजपा के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। गत 10 दिसंबर, 2020 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रवास के दौरान उनके काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों ने हमले किए। वहीं, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थरों से हमले किए गए। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है।

राज्य में अराजकता और असहिष्णुता कायम : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन 10 दिसंबर 2020 को कोलकाता के वेस्टिन होटल में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर तृणमूल कांग्रेस सरकार की अराजकतावादी नीतियों पर हमला करते हुए लोगों से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने और भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री नड्डा ने अपने काफिले पर तृणमूल कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों द्वारा किये गए वीभत्स हमले की निंदा करते हुए कहा कि आज जो घटना घटित हुई वह ममताजी की बौखलाहट की कहानी बयां करती है। ममताजी को दिख चुका है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। आज की घटना यह भी दिखाती है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और अराजकता और असहिष्णुता कायम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी राजनीतिक बहस की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ममता सरकार काम कर रही है वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है और साफ तौर पर दिखाती है कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता सरकार है। उन्होंने कहा कि आज हमारे काफिले पर हुए हमले में हमारे आठ बच्चे घायल हो गए, ये बच्चे बंगाल के थे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय उनके साथ खड़ा रहेगा। श्री नड्डा ने कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं। हम बंगाल के हर क्षेत्र में जाएंगे और अपने विचार रखेंगे। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं कि किस तरह से आज उनको पीटा गया, मोटर साइकिल गायब कर दी गईं। लेकिन हमारा एक-एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल में फिर से प्रजातंत्र को बहाल करेंगे।

श्री नड्डा ने प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले एक साल में भाजपा के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जिसमें सौ कार्यकर्ताओं का तर्पण स्वयं मैंने कोलकाता आकर किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक कारणों से हत्या हुई, इसे बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए वीभत्स हमले निंदनीय: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 दिसंबर, 2020 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुए वीभत्स हमले की निंदा करते हुए गहरा दुःख व्यक्त किया है और कहा कि केंद्र सरकार इस हमले को बेहद गंभीरता से ले रही है।

श्री शाह ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी भी निंदा की जाये वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा।

श्री शाह ने अपने अन्य दूसरे ट्वीट के माध्यम से पश्चिम बंगाल की अराजकतावादी और असहिष्णु सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल शासन में पश्चिम बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुःखद भी है और चिंताजनक भी। ■

हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 19 दिसंबर, 2020 को मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड, मिदनापुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से भ्रष्टाचार और अराजकता की पर्यायवाची बन चुकी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जड़ से उखाड़कर विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया। सबसे पहले श्री शाह ने कोलकाता स्थित श्री रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात् उन्होंने मिदनापुर के प्रसिद्ध मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। वे वीर शहीद खुदीराम बोस के घर भी गए और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात् उन्होंने देवी महामाया मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पूजा-अर्चना के बाद वे मेदिनीपुर के बेलिजुरी गांव गए और किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन किया।

मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा में जनता का उत्साह देखते ही बनता था। 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के नारों से पूरा मिदनापुर गुंजायमान हो रहा था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सरकार में मंत्री रह चुके श्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने सहयोगियों के साथ गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंच पर श्री शाह के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल रॉय, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल सिन्हा, केंद्रीय मंत्री सुश्री देबोश्री चौधरी, सांसद श्री ज्योतिर्मय महतो, सुश्री लॉकेट चटर्जी, श्री सौमित्र खान, राज्य सभा सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, भारती घोष, सान्याल दत्ता भी उपस्थित थे। श्री शाह के साथ इस जनसभा के केंद्र बिंदु श्री शुभेंदु अधिकारी भी थे जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कई विधायकों, सांसद, जिला परिषदों और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने मंच पर श्री शुभेंदु अधिकारी जी का हार्दिक स्वागत किया।

• जब तक पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देती, तब तक प्रदेश में न तो गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है और न ही किसानों को किसान सम्मान निधि का ही लाभ मिलने वाला है

श्री शाह ने पश्चिम बंगाल की पावन धरा को नमन करते हुए कहा कि मिदनापुर की यह भूमि महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और वीर शहीद खुदीराम बोस की जन्मभूमि है। मैं आज शहीद खुदीराम बोस के घर जाकर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां की माटी को अपने कपाल पर लगाकर आया हूं। मैं उनकी भूमि को बारंबार नमन करता हूं। मैं साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, पूर्व सांसद सतीश जी एवं जन संघ के हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय दुर्गाचरण बनर्जी जी का भी पुण्य स्मरण करता हूं। उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ एक सांसद, नौ विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक राज्य मंत्री, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमेन और जिला पंचायत के दो अध्यक्ष जुड़े हैं। श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, कम्युनिस्ट–सभी पार्टियों से अच्छे लोग आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। मैं उन सबका हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं।

ममता बनर्जी पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि दीदी को 10 करोड़ बंगाली जनता का भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, करोड़ों युवाओं का भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। उनकी नजर में उनका भतीजा ही सब कुछ है, वे हमेशा इसी बात में रहती हैं कि अपने भतीजे को

मुख्यमंत्री कैसे बनाएं। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से पूछने आया हूं कि पश्चिम बंगाल के युवाओं का क्या दोष है कि प्रदेश का विकास नहीं हो रहा। मैं पूछने आया हूं पश्चिम बंगाल के किसानों से कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दे रहे हैं, वह पश्चिम बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को लगभग 95,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक मिल चुकी है लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों को एक भी रुपया नहीं मिला। क्योंकि ममता दीदी लाभार्थी किसानों की सूची ही केंद्र को नहीं भेजती। देश भर की गरीब जनता को पांच लाख रुपये तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देते हैं। ये सुविधा पश्चिम बंगाल की गरीब जनता को भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ममता दीदी राज्य में इस योजना को लागू ही नहीं होने देती। जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और जब तक राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंक नहीं देती, तब तक प्रदेश में न तो गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है और

पश्चिम बंगाल की बदहाली की जिम्मेवारी किसकी?

- जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त देश की जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा पश्चिम बंगाल का हुआ करता था और आज वह घटकर एकदम नीचे चली गई है। लगभग तीन दशक के कम्युनिस्ट शासन और एक दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन में यह ग्राफ गिरता ही चला गया। इसकी जिम्मेवारी किसकी है?
- आजादी के वक्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल का योगदान 30% था जो आज घट कर 3.5 पर्सेंट रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी से कि इसका जिम्मेदार कौन है? रोजगार में 1960 में पश्चिम बंगाल का सेटिस्फेक्शन रेशियो पहले 27% था, वह 4% पर आ गया है। इस गिरावट का जिम्मेदार कौन है?
- 1960 में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय से 105% अधिक थी अर्थात् महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय का लगभग दोगुना थी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की आधी भी नहीं रह गई है। 2018-19 में देश के 32 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की सूची में करेंट मूल्यों के आधार पर पश्चिम बंगाल 22वें स्थान पर रहा जबकि स्थिर मूल्यों के आधार पर 24वें स्थान पर रहा। कौन जिम्मेवार है इसका?
- एक समय था, जब पश्चिम बंगाल में बंदरगाहों पर आवाजाही लगभग 42% हुआ करती थी जो आज घट कर केवल 10% रह गया है, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका?
- 50 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडॅक्ट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता था जो आज गिरकर मात्र 7% रह गया है, कौन जिम्मेदार है?
- पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किसानों, मजदूरों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था लेकिन आज अधिकांश जूट मिलें बंद है। आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है?
- भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 2011-12 में पश्चिम बंगाल 6.03 पर पहुंच गया। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि के संदर्भ में पश्चिम बंगाल 32 राज्यों की सूची में 20वें स्थान पर है। सेवा के क्षेत्र में वृद्धि के मामले में यह केवल 5.8% पर है और राज्यों की सूची में 28वें स्थान पर है।
- राज्य के स्वयं के राजस्व की वृद्धि में पश्चिम बंगाल 2011-12 और 2019-20 के मध्य 31 राज्यों की सूची में 16वें स्थान पर रहा।
- एक आंकड़े के अनुसार पश्चिम बंगाल में जो भी बच्चा जन्म लेता है, वह 50 हजार रुपये के कर्ज के साथ जन्म लेता है। अन्य राज्यों में कर्ज ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अन्य राज्यों में विकास भी हुआ है जो पश्चिम बंगाल में कहीं दिखाई नहीं देता। यहां सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, पता नहीं चलता।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बंगाल की हिस्सेदारी 2011 में भी 1% थी, आज 2020 में भी 1% ही है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले में पश्चिम बंगाल में 58% कमी है जबकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 36% की कमी है। प्रति हजार लोगों पर उपलब्ध बेड की संख्या के आधार पर भी पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी निराशाजनक है, यह 23वें स्थान पर है। आखिर यह किसकी जिम्मेवारी है?
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए लगभग 39% स्थान खाली है। स्पेशियलिटी और सर्जन के लिए लगभग 87% स्थान खाली है।
- शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो ग्रांट भेजी है, वह भी पश्चिम बंगाल में खर्च नहीं हो पाया।
- शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में 90% प्राथमिक स्कूलों में डेस्क नहीं है। लगभग 30% से ज्यादा स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं है। 10% स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है और 56% स्कूलों में शौचालय नहीं है। प्रति एक लाख की जनसंख्या पर केवल 13 कॉलेज हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल 32 राज्यों की सूची में 28वें स्थान पर है।

न ही किसानों को किसान सम्मान निधि का ही लाभ मिलने वाला है।

श्री शाह ने ने कहा कि आज मैंने एक किसान परिवार के घर पर भोजन करके आया हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है तो उन्होंने कहा कि अब तक नहीं मिला है। फिर मैंने उनसे पूछा कि घर कैसे बनाया, क्या इसके लिए लोन लेना पड़ा तो किसान बंधु ने बताया कि घर बनाने के लिए लोन नहीं लेना पड़ा, यह श्री नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। पश्चिम बंगाल की गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो करना चाहते हैं, उसमें तृणमूल सरकार सबसे बड़ी बाधा बन कर खड़ी है।

तृणमूल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए श्री शाह ने कहा कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के विकास का वादा किया था लेकिन राज्य का विकास तो हुआ नहीं, मगर यहां पर टोलबाजी और अराजक तत्वों को राजनीतिक शरण मिली। ममता दीदी, आपने पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का वादा किया था लेकिन अम्फान तूफ़ान के पीड़ितों के लिए जो सहायता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भेजी, उसे भी आपके समर्थित लोग हड़प कर गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोरोना कालखंड में पश्चिम बंगाल की गरीब जनता के लिए 8 महीनों तक जो मुफ्त अनाज भेजे, उसे भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हड़प ले गए, गरीब जनता को कुछ भी मिल नहीं पाया। यहां तक कि इस मामले में हाईकोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच कराई जाए। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए कि गरीब के पेट का अनाज आपके कार्यकर्ता लूट ले गए। इसलिए, पश्चिम बंगाल की जनता आपको नहीं चाहती।

श्री शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आपने राज्य में तीन दशकों तक कांग्रेस को मौक़ा दिया, 27 वर्षों तक वामपंथी पार्टियों को मौक़ा दिया, ममता दीदी को भी 10 वर्ष का समय दिया। अब आप एक पांच वर्ष का सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को भी दीजिए, हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे।

दूसरा दिन

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 20 दिसंबर, 2020 को बीरभूम, पश्चिम बंगाल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और विभिन्न विषयों पर तृणमूल कांग्रेस की पोल खोलते हुए ममता बनर्जी सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला। उन्होंने पश्चिम बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाने के भारतीय जनता पार्टी सरकार के उद्देश्य को दोहराते हुए प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की। इससे पहले उन्होंने आज श्यामबती, पारुलडांगा (बीरभूम)

में बाउल गायक परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया और बोलपुर (बीरभूम) में हनुमान मंदिर, स्टेडियम रोड से बोलपुर सर्कल तक भव्य रोड शो किया। रोड शो में अपार भीड़ उमड़ी। पूरा बोलपुर 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारों से गुंजायमान हो रहा था। जहां तक भी नजर जा रही थी, हर जगह भाजपा का झंडा ही झंडा और भगवा साफा पहने लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे।

> **"आपने राज्य में तीन दशकों तक कांग्रेस को मौक़ा दिया, 27 वर्षों तक वामपंथी पार्टियों को मौक़ा दिया, ममता दीदी को भी 10 वर्ष का समय दिया। अब आप एक पांच वर्ष का सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को भी दीजिए"**

रोड शो में जनता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मैंने कई रोड शो किये हैं और देखे हैं, लेकिन आज के जैसा रोड शो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि इस बार के विधान सभा चुनाव में वह राज्य की सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को देगी। ये रोड शो पश्चिम बंगाल की जनता का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अटूट विश्वास को दिखाता है। साथ ही, यह रोड शो पश्चिम बंगाल की जनता का ममता दीदी के प्रति गुस्से का भी प्रतीक है। 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के उद्घोष के बीच उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों ने 'पोरिबर्तन' (बदलाव) का फैसला कर लिया है लेकिन ये बदलाव सिर्फ व्यक्ति का बदलाव नहीं बल्कि प्रदेश के विकास के लिए है।

उन्होंने रोड शो में उमड़े विशाल जन-समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आपने कांग्रेस को मौक़ा दिया, कम्युनिस्टों को मौक़ा दिया और तृणमूल कांग्रेस को भी बहुत समय दिया। आप सेवा का एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को भी दीजिये, हम पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाकर रहेंगे। हम पश्चिम बंगाल को देश के महान सपूतों नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर के सपनों का बंगाल बनायेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक रोड शो में उपस्थित भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और भाजपा की तरफ से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को दी मंजूरी

इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों को होगा लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 16 दिसंबर को गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दी। इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।

इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।

किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी।

सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (एमएईक्यू) के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा 'पीएम वाणी' को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर को टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा।

विशेषताएं

सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा 'पीएम वाणी' के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जैसाकि निम्न उल्लेख किया गया है:

- **पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ):** यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।
- **पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ):** यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे।
- **ऐप प्रदाता:** यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई-फाई वाले हॉट स्पाट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरुप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे, ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें।
- **सेंट्रल रजिस्ट्री:** यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा।

उद्देश्य

पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। ये लोग सरल संचार; (https://saralsanchar.gov.in) वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा।

यह व्यवस्था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी, खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरूरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा, जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। ■

बैक टू बैक लोन के तौर पर राज्यों को जारी की गई 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं किस्त

कानूनी प्रावधानों के साथ सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक कुल 42,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इसमें से कुल 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी), जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, को जारी की गई है। शेष 5 राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम– में जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है।

वित्त मंत्रालय की 14 दिसंबर को जारी एक रपट के अनुसार भारत सरकार ने जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में पैदा हुई 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर, 2020 में एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था की थी।

भारत सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से इस खिड़की के जरिए उधार लिया जा रहा है। ये उधारियां 7 चरणों में की गई हैं। अब तक उधार ली गई राशि क्रमशः 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020, 23 नवंबर, 2020, 1 दिसंबर, 2020, 7 दिसंबर, 2020 और 14 दिसंबर, 2020 को राज्यों को जारी की गई हैं।

इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 7वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 5.1348% की ब्याज दर पर उधार ली गई है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 4.7712% की औसत ब्याज दर पर विशेष उधार खिड़की के जरिए कुल 42,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।

जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष उधार खिड़की के जरिए धन प्रदान करने के अलावा भारत सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए विकल्प–1 का चुनाव करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% के बराबर की राशि अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति भी दी है।

सभी राज्यों ने विकल्प-1 के प्रति अपनी प्राथमिकता जतायी है। इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50%) की संपूर्ण अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है। ■

डीआरडीओ हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन

अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के मामले में इतनी बड़ी सुविधा है

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर, 2020 को डीआरडीओ हैदराबाद में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल (एचडब्ल्यूटी) परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक एचडब्ल्यूटी टेस्ट सुविधा है। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के मामले में इतनी बड़ी सुविधा है।

यह सुविधा स्वदेशी रूप से विकसित और भारतीय उद्योगों के साथ की गई साझेदारी का एक परिणाम है। इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह अत्यधिक जटिल फ्यूचररिस्टिक एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने मिसाइल, एवियोनिक्स सिस्टम, एंडवांस्ड मैटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रमुख वितरण प्रौद्योगिकी, निर्देशित ऊर्जा हथियार, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी क्षमताओं सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकसित विभिन्न स्वदेशी प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।

रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा दो ड्रोन विरोधी तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया। डीआरडीओ युवा वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला- असममित प्रौद्योगिकी (डीवाईएसएल-एटी) और आरसीआई ने ड्रोन और नवीन एंटी-ड्रोन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। इसमें मुकाबला करने के लिए ग्राउंड टारगेट और एंटी-ड्रोन एप्लिकेशन को बेअसर करने के साथ-साथ हाई-स्पीड मूविंग टार्गेट सहित कई क्षमताएं शामिल हैं। हथियार प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में सुरक्षित संचार लिंक, प्रभावी पुनरावृत्ति प्रबंधन प्रणाली, उच्च फायरिंग कोणीय संकल्प और दृष्टि-आधारित लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग शामिल हैं। ■

27 राज्यों ने 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना' का उठाया लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों ने 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' की योजना का लाभ उठा लिया है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 12 अक्तूबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है, जो कोविड-19 महामारी की वजह से कर राजस्व में हुई कमी के कारण इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

इस योजना को राज्य सरकारों से बहुत जोरदार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों को पहले ही 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है।

इस योजना के तीन हिस्से हैं। योजना का भाग-1 पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करता है। इस हिस्से के तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिक आबादी और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए असम को इस योजना के तहत 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• वित्त मंत्रालय द्वारा अभी तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों को पहले ही 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है

योजना का भाग-2 अन्य सभी राज्यों के लिए है, जिन्हें भाग-1 में शामिल नहीं किया गया है। इस भाग के लिए 7500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि का आवंटन इन राज्यों के बीच वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की अंतरिम मंजूरी के अनुरूप केन्द्रीय कर के उनके हिस्से के अनुपात में किया गया है।

योजना के भाग-3 का लक्ष्य राज्यों में विभिन्न लोक केन्द्रित सुधारों को बढ़ावा देना है। इस भाग के तहत 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि केवल उन्हीं राज्यों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने सुधार संबंधित अतिरिक्त उधारी अनुमतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा 17 मई, 2020 के अपने पत्र में निर्दिष्ट चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार कार्यान्वित किए हैं। ये चार सुधार हैं- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार तथा बिजली क्षेत्र सुधार। ■

2927 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ई-अदालत परियोजना के तहत देशभर के लगभग 2927 अदालत परिसरों को अभी तक तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ा जा चुका है। परियोजना के तहत 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति डब्ल्यूएएन से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसका 97.86 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है। विधि विभाग बीएसएनएल के साथ मिलकर शेष अदालत परिसरों को भी संपर्क मुहैया कराने के काम में संलग्न है।

ई-अदालत परियोजना के तहत विधि विभाग ने विश्व के एक सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क को स्थापित करने की परिकल्पना की थी और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के साथ मिलकर देशभर के 2992 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाले वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था।

इन अदालत परिसरों को ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वीसेट) इत्यादि से जोड़ा जाना था। मई, 2018 में इन सभी परिसरों को मैनेज्ड एमपीएलएस–वीपीएन सेवा से जोड़ने का कार्य बीएसएनएल को सौंपा गया था, जिसके पास आधुनिकतम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकी के साथ ही अत्याधुनिक दूरसंचार अवसंरचना और ट्रांसमिशन उपकरण हैं और जिसकी देशभर में उपस्थिति है।

ई-अदालत परियोजना के तहत आने वाले बहुत से अदालत परिसर ऐसे दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं जहां संपर्क उपलब्ध कराने के लिए स्थलीय केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे इलाकों को तकनीकी तौर पर नहीं जुड़ने योग्य (टीएनएफ) कहा जाता है और विधि विभाग ने इस डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए इन टीएनएफ स्थलों पर आरएफ और वीसेट आदि जैसे वैकल्पिक माध्यमों से संपर्क उपलब्ध कराया। ■

अपनी विचारधारा सहयोग पर आधारित

दीनदयाल उपाध्याय

हम अपने राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। या जैसे कि प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हम उसकी सर्वांगीण उन्नति देखना चाहते हैं। वैभव की यह अवस्था कैसी होगी? उन्नति की यह स्थिति कैसी होगी? इसकी कुछ कल्पना भी हमने प्रतिज्ञा और प्रार्थना दोनों में करके रखी है। वह अपने धर्म के आधार पर, क्योंकि हमने यह कहा है कि इस धर्म की रक्षा करते हुए हम इसे परम वैभव पर ले जाएं अर्थात् यदि धर्म का विस्मरण कर दिया और यह कल्पना भी कर लें कि हमें किसी भी प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया तो हम उसे नहीं मानेंगे।

दूसरी बात जो इससे भी अधिक सत्य है कि राष्ट्र का वैभव बिना धर्म का आधार लिए प्राप्त नहीं हो सकता। बिना धर्म की रक्षा किए वह वैभव नहीं मिल सकता। किसी वस्तु का वैभव उसके धर्म को भुलाकर कभी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार अपने राष्ट्र के वैभव के संबंध में, इसके साथ ही हमने यह विचार किया था कि जब हम इस धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी सामान्य कल्पना क्या है? उसके नाते धर्म की जो एक व्याख्या हमने की, उसका आधार यह कि धारणा से धर्म शब्द प्रचलित हुआ था। जिससे धारणा होती है, जिस शक्ति से, जिस तत्त्व से, जिस प्रवृत्ति से, जिस व्याख्या से जिस किसी भी चीज़ की धारणा हो सके वह धर्म है। प्रजा की धारणा भी होती है और इस नाते से हम किस आधार पर टिके हुए हैं, जब इसका विचार किया तो उसमें यह भी देखा कि शरीर को टिकाए रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक हैं, वह सब धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। समाज कार्य के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वह समाज धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। समाज और शरीर इन सबको टिकाए रखने के लिए जितनी भी चीजें ज़रूरी हैं, वे सब अपने धर्म के, सृष्टि के अंतर्गत आ जाएंगी। इस प्रकार से यह धर्म केवल उसकी एक इकाई है। जो भिन्न-भिन्न इकाइयां हैं, इन सब इकाइयों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। यदि उसके बीच में कोई संघर्ष आ गया, कोई विरोध उत्पन्न हो गया, किसी भी कारण क्यों न हो, विरोध को मिटाकर उसके स्थान पर समन्वय करके धर्म की प्रतिष्ठापना करना, उसके लिए प्रयत्न करना और दोनों प्रकार की इकाइयां, सभी इकाइयां सामान्य आधार के ऊपर अपना विचार प्रकट कर सकें, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें, एक-दूसरे के साथ पूरकता के भाव से काम कर सकें, वह काम ही वास्तव में धर्म का काम है।

जैसे यदि एक व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं तो शारीरिक दृष्टि से उसकी जो इंद्रियां हैं, वे एक-दूसरे के लिए पूरक हैं। सबका योग्य विकास हो सके, आपस में संघर्ष न आए, वैसे ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई संघर्ष न आए और जो व्यक्तियों के समूह बनते हैं, उनके बीच में कोई संघर्ष न आए। विभिन्न प्रकार के बने हुए व्यक्तियों के समूहों के बीच में संघर्ष न आए। संपूर्ण प्राणिमात्र और मानव उनके बीच किसी प्रकार का संघर्ष उपस्थित न हो। संपूर्ण प्राणी जगत् और प्रगति के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष उपस्थित न हो, बल्कि सब एक-दूसरे के लिए पूरकता का भाव लेकर विकास के लिए विचार करते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार की यह स्थिति सामान्य है। हमारा धर्म एकांगी नहीं, वह तो सर्वांगीण है, व्यापक है, सबका विचार करके चलने वाला है। यह हम लोगों का सामान्य विचार रहा है।

अन्य दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में और भी विचार हैं। पश्चिम के भी अनेक विचार हैं। अनेक विचारों के साथ तथा हमारे इस विचार के साथ मूलतः एक मतभेद खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इस प्रकार से एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच सामंजस्य मानकर चलते हैं। परंतु पश्चिम में जो प्रमुख विचार हुआ है, वह यह कि उनके सभी प्रयत्नों में विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य नहीं। वहां उन्होंने विरोध को प्रथम स्थान देकर रखा है। उनकी सामान्य कल्पना संपूर्ण जीवन के संबंध में यह रही है कि मानव का जीवन संघर्षमय है। इस संघर्ष में से ही कुछ पीढ़ियां समाप्त होती चली जाती हैं। बाक़ी जो हैं, वही प्रगति करती चली जाती हैं। सृष्टि भी इसी संघर्ष के आधार पर खड़ी हुई है। यानी वहां के जीवन में आधार पर विचार करें। अंग्रेजी में एक शब्द को लें तो उनकी संपूर्ण Philosphy Competition (प्रतिस्पर्धा) के ऊपर आधारित है। यही उनका विचार चलता है। अपनी जितनी भी विचारधारा है, वह सहयोग के ऊपर आधारित है। पूरकता पर आधारित है। यहां पर Competition का विचार नहीं है। जीवन का आधार Co-operation है। सहयोग, सहकारिता आधार है। पूरकता का आधार है, इसको हम मानकर चलते हैं।

वहां इस प्रकार का विचार न करके उन्होंने Competition

के विचार को ही प्रमुखता आज भी दी है। दूसरी बात जो उन्होंने विचार किया है वह यह किया है, कि जहां हम प्रत्येक इकाई का विचार उसकी पूर्णता को देखने में करते हैं, वहां उन्होंने इकाई को पूर्णता की दृष्टि से नहीं देखा। उदाहरण के लिए यदि शरीर को लें तो हम व्यक्ति के शरीर को केवल भौतिक आवश्यकताओं का पुंज मात्र मानकर नहीं चलते। भौतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ उसकी और कौन-कौन सी आवश्यकताएं भी हैं, उसकी सब प्रकार की हस्तियां हैं। इस वस्तु को मानकर हम चलते हैं, परंतु पश्चिम के अनेक लोग केवल भौतिक दृष्टि से तैयार रहें, जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसी के संबंध में विचार होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा विचार ही नहीं आता। भौतिक और बाक़ी की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को प्रमुखता व बाक़ी को गौण स्थान देकर वे चलते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष आते हैं और आ सकते हैं। यह उनका स्वाभाविक और सामान्य विचार है। यदि इस प्रकार के संघर्ष आकर खड़े हो जाते हैं तो वह एक असामान्य स्थिति है। वह धर्म की स्थिति नहीं है, तो एक प्रकार से विकृति की स्थिति है। ऐसा हम विचारकर चलते हैं। जैसे कि अपने दोनों पैर हैं। दोनों पैर भगवान् ने इसलिए बनाए कि वे ठीक प्रकार से चलें। आपस में लड़ते नहीं, टकराते भी नहीं, और दोनों पैरों का उपयोग भी हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। दोनों पैरों में कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, इसका विचार नहीं करते, झगड़ा भी नहीं होता।

• अंग्रेजी में एक शब्द को लें तो उनकी संपूर्ण Philosphy Competition **(प्रतिस्पर्धा) के ऊपर आधारित है। यही उनका विचार चलता है। अपनी जितनी भी विचारधारा है, वह सहयोग के ऊपर आधारित है। पूरकता पर आधारित है। यहां पर** Competition **का विचार नहीं है। जीवन का आधार** Co-operation **है। सहयोग, सहकारिता आधार है। पूरकता का आधार है, इसको हम मानकर चलते हैं।**

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य यदि कमज़ोर हो गया तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जिन पैरों का काम यह है कि मनुष्य के संपूर्ण शरीर के बोझ को संभालकर चलें, जिन पैरों का काम संतुलन बनाए रखना है, वे पैर भी उसके संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ऐसी स्थिति कभी-कभी आती है, परंतु वह स्थिति हमारी कमज़ोरी के कारण होगी। आहार-व्यवहार में कुछ बिगाड़ से उत्पन्न हुई, किंतु यह सामान्य स्थिति नहीं। यह असामान्य स्थिति है और उस असामान्य स्थिति को दूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए यदि कोई इस असामान्य स्थिति को सामान्य स्थिति कहकर चले और यही सोचकर चले कि पैरों का काम ही लड़खड़ाने का है। पैर लड़खड़ाएं नहीं, इसलिए लकड़ी की पट्टी बांध दें, यदि इस प्रकार का कोई विचार करके चलेगा, तो मूलतः वास्तव में अलग विचार होगा। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य जगत् के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ इसी आधार पर अपने संपूर्ण जीवन की रचना की है और उसमें फिर अपना-अपना स्वार्थ रखकर दोनों के बीच प्रतियोगिता को आधार बनाकर प्रतिदिन बराबर करते गए और उसमें से व्यक्ति और समाज के बीच एक संघर्ष खड़ा किया। पश्चिम के लोग व्यक्ति और समाज के बीच एक संघर्ष खड़ा है, ऐसा मानकर चलते हैं। इसलिए आज वहां पर दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं : एक ऐसे, जो व्यक्ति को प्रमुखता देकर समाज को पीछे डालकर कहते हैं कि व्यक्ति प्रमुख है। समाज जो कुछ करेगा, व्यक्ति के हितों के लिए करेगा और समाज को वहीं तक मानने को तैयार हैं, जहां तक व्यक्ति के लिए वह सहायक है। इस प्रकार का विचार रखनेवाले लोग पश्चिम जगत् में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ़ ऐसे लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं कि यदि कुछ व्यक्तियों ने गड़बड़ की तो उस गड़बड़ के आधार पर यह मानकर कि सारे व्यक्ति खराब हैं और यह व्यक्ति समाज के संबंध में विचार नहीं कर सकते, ये लोग दूसरों के हित का विचार नहीं कर सकते, इसलिए इनकी सत्ता को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। वे समाज को ही प्रमुख स्थान देकर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानकर चलते हैं, व्यक्ति को मान का स्थान दिया तो समाज समाप्त हो जाएगा। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि समाज को प्रमुखता दी, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज का हित—ये दोनों मानो साथ नहीं चल सकते। दोनों में से हमें एक को चुनना पड़ेगा। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए तो समाज के हित की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज के हित की सोचने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में समाज को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार का विचार करनेवाले लोग वहां पर पैदा हो गए।

वे सही विचार नहीं करते हैं। मानव और बाक़ी के अन्य प्राणियों—इन सबके बीच मानो एक प्रकार का संघर्ष है। संघर्ष में मानव को अधिकार है, सभी अन्य प्राणियों का उपयोग अपने लिए करे। अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई है, केवल शक्ति की होड़ है। डार्विन ने विचार किया और कहा कि यहां पर Survival है। जो योग्य हैं, वही ठीक क्रम में हैं, बाक़ी जितने अयोग्य हैं, एक-दूसरे को खाते चले जाते हैं। अपने जीवन को बनाए रखने की लड़ाई और इस लड़ाई में संघर्ष ही इसका प्रमुख आधार है। कुछ और आगे विचार करते चले जाएं तो यह देखेंगे कि उनकी दृष्टि में मनुष्य और प्राणियों के बीच तथा मनुष्यों में संपूर्ण मानव समाज, छोटे-छोटे गुट हैं, राष्ट्र हैं और राष्ट्रों में और राष्ट्र और व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति की भी जो अनेक प्रकार की हस्तियां हैं, उन सबके बीच में मानो एक परमानेंट संघर्ष की स्थिति है। ■

क्रमशः

-संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : हरिगढ़ (5 जून 1962)

नहीं रहे विचारक माधव गोविंद वैद्य

(11 मार्च, 1923 – 19 दिसंबर, 2020)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ विचारक और संगठन के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य (बाबूराव) का 19 दिसंबर को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 मार्च, 1923 को जन्मे श्री वैद्य को 'संघ का विश्वकोश' के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने संगठन को विश्व के सामने एक बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया। श्री वैद्य देश के संस्कृत भाषा के विद्वानों में शुमार थे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत कम जीवित लोगों में से एक थे, जिन्होंने संघ के सभी छह सरसंघचालकों के साथ काम किया। उन्होंने एक सक्रिय, सार्थक और प्रेरक जीवन जीया। वे आठ साल में ही संघ के स्वयंसेवक बन गए तथा 95 वर्ष की आयु तक शाखा में भाग लेते रहे।

शोक संदेश

श्री माधव गोविंद वैद्य के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक शोक संदेश में कहा कि संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान, उत्तम पत्रकार, विधान परिषद के सक्रिय सदस्य, उत्कृष्ट साहित्यिक, ऐसी सारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बाबूराव जी ने यह सारी गुण संपदा संघ में समर्पित कर रखी थी। वे संघ कार्य विकास के सक्रिय साक्षी रहे। उनका जीवन व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा आजीविका इन चतुर्विध आयामों में संघ संस्कारों की अभिव्यक्ति करने वाला संघानुलक्षी, संपन्न व सुंदर गृहस्थ जीवन था। सरल भाषा में तर्कशुद्ध रीति से व अनुभूतिमूलक विवेचन से संघ को अपनी वाणी और लेखनी द्वारा वे जगत में सर्वत्र प्रस्तुत करते रहे। संघ ने शोक संदेश में कहा कि श्री वैद्य जी का पूरा परिवार आज एक विस्तृत छत्रछाया का अभाव अनुभव कर रहा है। हम सबका तथा उनका सांत्वन करना कठिन है। समय ही उसका उपाय है। बाबूराव जी का जीवन हम सबको हर अवस्था में अपने कर्तव्य पालन का कार्य अविचल और अडिग रीति से करना सिखा रहा है।

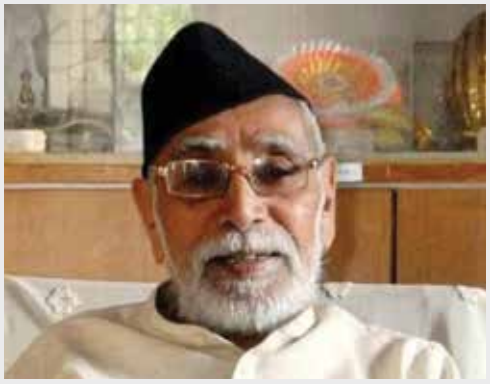

श्री वैद्य के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि श्री एमजी वैद्य जी एक प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने दशकों तक संघ में व्यापक रूप से योगदान दिया। उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए भी काम किया। उनके निधन से दुःखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते कहा कि श्री एमजी वैद्य ने मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे जीवनपर्यंत सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रयासरत रहे। उनका जाना संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। ■

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद श्री सत्यदेव सिंह का 17 दिसंबर को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। खराब स्वास्थ्य के कारण उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री सत्यदेव सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

उन्होंने 1980 से 1985 तक भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। वह सादगी और पारदर्शी राजनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1977 में पहली बार गोंडा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में वे 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। राम मंदिर आन्दोलन में भी देवीपाटन मंडल से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ■

स्थानीय निकाय चुनावों में खिला कमल

देश भर में हो रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज कर रही है। चाहे जम्मू-कश्मीर के जिला विकास परिषद का चुनाव हो, राजस्थान के पंचायत राज और जिला समिति चुनाव हो, असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) का चुनाव हो, अरुणाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद् के चुनाव हो, गोवा का जिला पंचायत चुनाव हो, लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव हो या फिर केरल का निकाय चुनाव; हर जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय और कांग्रेस की करारी हार हुई। कृषि सुधार कानून के बाद हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई क्योंकि देश के गांव, गरीब, किसान और मजदूर मोदी सरकार और भाजपा के साथ हैं

जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव, जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह अपने-आप में जम्मू-कश्मीर के बदलते बयार को रेखांकित करता है। डीडीसी चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 75 सीटें जीती जबकि अन्य कोई भी पार्टी अकेले इस आंकड़े के पास भी नहीं पहुंच पाई। नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) 67, पीडीपी सिर्फ 27 और कांग्रेस किसी तरह 26 सीटें जीत पाई। 49 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कामयाबी मिली जिसमें कई उम्मीदवार भाजपा के समर्थन से विजयी हुए। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिलाकर पाए गए वोट से ज्यादा वोट मिले। जहां भाजपा को लगभग 4.87 लाख वोट मिले हैं वहीं एनसी को 2.82 लाख, पीडीपी को सिर्फ लगभग 56 हजार और कांग्रेस को 1.39 लाख वोट मिले। इस तरह, भाजपा को कुल 38% और गुपकार गठबंधन को केवल 32% वोट मिले हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गुपकार गठबंधन में आठ छोटी-बड़ी पार्टियां हैं जो केवल भाजपा से मुकाबले के लिए एकजुट हुई थीं।

पार्टी	कुल जीती हुई सीटें	कुल मतदान
भाजपा	75	487364
जे एंड के एनसी	67	282514
स्वतंत्र	49	171420
जे एंड के पीडीपी	27	55789
कांग्रेस	26	139382
जेकेएपी	12	38147
जेकेपीसी	8	43274
सीपीआई(एम)	5	6407
जेकेपीएम	3	6754
पीडीएफ	2	7273
जेकेएनपीपी	2	12137
बीएसपी	1	7397

डीडीसी चुनाव में कुल आठ चरणों में संपन्न हुए चुनाव में 51% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जहां लोग वोट डालने दहशत के मारे घरों से निकलते भी नहीं थे, वहां भी जमकर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुलगाम, शोपियां और पुलवाम जैसे इलाकों में भी जमकर वोटिंग हुई। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर जो अलगाववाद से ग्रस्त था, वहां पर भी भारी संख्या में मतदान हुआ। बांदीपोरा, बडगाम, गांदरबल जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जमकर वोटिंग हुई। लोक सभा चुनाव में इन क्षेत्रों में काफी कम वोटिंग हुई थी लेकिन धारा 370 हटने के बाद लोकतंत्र में अवाम की आस्था दृढ़ हुई है और वे अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं।

विकासवादी विचारधारा में विश्वास का प्रतीकः जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 23 दिसंबर, 2020 को जम्मू-कश्मीर जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती और इसमें वहां की जनता के दृढ़ होते विश्वास का परिचायक है।

श्री नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए मैं जम्मू-कश्मीर की अवाम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने मत के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, नीतियों और लिए गए निर्णयों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे और परिश्रम की पराकाष्ठा पार करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश भाजपा की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण एवं चहुंमुखी विकास के साथ-साथ यहां की जनता को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर की वंदनीय जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में इतनी बड़ी संख्या में भाग लेकर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के सिद्धांत में अपना संपूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। यह वाकई काबिलेतारीफ है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिला हर वोट जम्मू-कश्मीर की जनता का देश की विकासवादी विचारधारा में विश्वास का प्रतीक है। ■

यह लोकतंत्र की जीत हैः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के अवाम की जीत है। साथ ही, यह जम्मू-कश्मीर के आने वाले सुनहरे कल की आशा और इसके प्रति यहां जनता के विश्वास की जीत है।

श्री शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर डीडीसी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए मतदान करने पर जम्मू-कश्मीर के भाइयों एवं बहनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव परिणाम कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा की स्वीकार्यता और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनता के अटूट विश्वास को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर के विकास एवं प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कटिबद्ध है और आगे भी निरंतर इसके लिए समर्पित भाव से कार्य करती रहेगी।

अगले ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि मैं इतनी भारी संख्या में जिला विकास परिषद के चुनाव में मतदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं। श्री शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार कटिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार हाल ही में संपन्न हुए डीडीसी चुनाव उसी की गवाही है। ■

"डीडीसी चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के कुल वोट से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। इस परिणाम, कुल मिलाकर 51.5% मतदान तथा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के साथ जम्मू और कश्मीर वापस पटरी पर है। जम्मू-कश्मीर भाजपा की टीम, रविंद्र रैना को बधाई।"

बीएल संतोष
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)

पंचायत राज और जिला समिति चुनाव, राजस्थान

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पंचायत समिति सदस्यों के घोषित 4371 परिणाम में भाजपा ने 1,990 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस को केवल 1,718 सीटों पर ही जीत मिल सकी। इसी तरह जिला परिषदों के अब तक घोषित परिणामों में भाजपा को 606 में से 353 सीटों पर विजय मिली जबकि कांग्रेस को केवल 250 सीटें ही मिल सकीं। 21 जिला प्रमुखों के लिए चुनाव में 14 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस केवल 5 सीट पर सिमट कर रह गई। 222 ब्लॉक पंचायतों में से भाजपा अब तक 93 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों ने दशकों के ट्रेंड को बदलकर रख दिया है। 2010 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस को 24 जिला परिषदों में सफलता मिली थी जबकि भाजपा को केवल 5 सीटें मिली थी। इसके बाद वसुंधरा सरकार में भाजपा को 21 जिला परिषद सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस को केवल 12 सीटें मिली थीं लेकिन इस बार प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की है लेकिन जीत की कहानी भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है और राज्य के मतदाताओं ने प्रदेश का ट्रेंड बदल दिया है।

बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव, असम

बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के चुनाव में भाजपा को शानदार सफलता मिली। पिछली बार के चुनाव में भाजपा को केवल एक सीट पर जीत मिली थी, जबकि इस बार भाजपा को 9 सीटों पर विजय मिली है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 40 सीटों वाली बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में भाजपा ने केवल 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल एक सीट पर जीत मिली है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल पहले कांग्रेस की हुआ करती थी।

ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। भाजपा ने जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त की। राज्य के जिला परिषद सदस्य की 242 सीटों में से भाजपा को 185 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और उसको महज 11 सीटें हासिल हुई तीसरे स्थान पर जदयू को नौ सीटें मिली जबकि एनपीपी को पांच सीटों से संतोष करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री श्री किरन रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है। भाजपा ने ग्राम सभा चुनावों में क्लिन स्विप किया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली यह शानदार जीत बताती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की लहर और भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन लगातार बना हुआ है।

जिला पंचायत चुनाव, गोवा

गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल की। भाजपा ने 33 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के खाते में चार सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सात, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने तीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक सीट

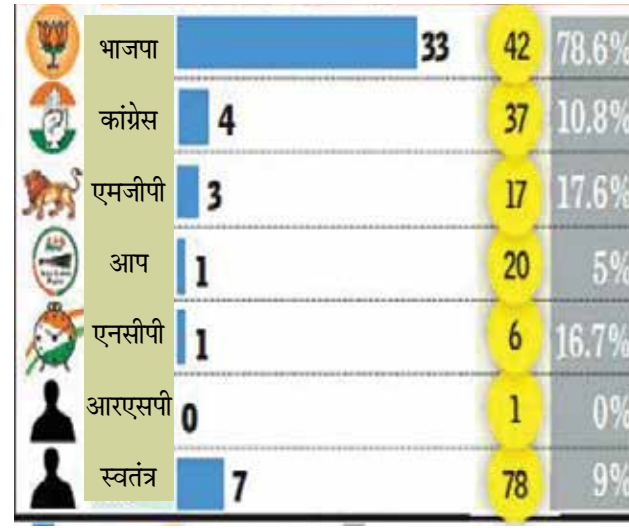

पर जीत दर्ज की। चुनाव में भाजपा का एक उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया। गोवा में मिली जीत पर मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं गोवा के लोगों को विनम्रतापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही मेरे नेतृत्व में काम कर रही गोवा सरकार पर भरोसा किया है।

लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव

लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव में भाजपा को शानदार विजय मिली। 26 सीटों वाली काउंसिल में भाजपा को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस केवल 9 सीटों पर ही सिमटकर रह गई। लद्दाख के भाजपा सांसद श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह हिल काउंसिल में भाजपा की जीत को गुपकार प्रस्ताव के मुंह पर करारा थप्पड़ बताया है। श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा कि अनुच्छेद 370, 35ए के खात्मे के बाद लद्दाख के राष्ट्रवादी लोगों ने भाजपा को शानदार जीत दिलाकर अपनी सोच उजागर कर दी है।

स्थानीय निकाय चुनाव, केरल

यहां भाजपा ने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

पार्टी ने 1,800 वार्डों में जीत हासिल की। प्रदेश भर के 600 वार्ड में वह दूसरे नंबर पर रही। 100 वार्ड वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में वह 32 वार्ड में दूसरे नंबर पर रही। अगर केरल के ग्राम पंचायतों की बात करें तो पार्टी ने 2015 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। 2015 में भाजपा ने 14 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल की, तो इस बार उसने 23 ग्राम पंचायतों पर परचम लहराया। इसी तरह नगरपालिकाओं और नगर निगमों में भी पार्टी ने अपने निर्वाचित सदस्यों की संख्या में अच्छा सुधार किया। उसने राज्य के नए इलाकों में अपनी पैठ बना ली है। एनडीए ने सेंट्रल त्रावणकोर और दक्षिणी केरल अपनी स्थिति मजबूत की। 2015 के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने केरल में 1,236 वार्ड में जीत दर्ज की थी और उसे 14 फीसदी वोट मिले थे। विदित हो कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 1,200 स्थानीय स्वशासी निकायों में छह नगर निगमों सहित कुल 21,893 वार्डों, 941 ग्राम पंचायतों, 14 जिला पंचायतों और 87 नगर पालिकाओं में आठ, 10 और 14 दिसंबर को तीन चरणों में मतदान हुआ था। ■

यह जम्मू-कश्मीर के अवाम की जीत है: रवि शंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने 23 दिसंबर 2020 को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस-वार्ता को संबोधित किया और जम्मू-कश्मीर जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव परिणाम में भाजपा की आशातीत सफलता के लिए जम्मू-कश्मीर की अवाम का अभिनंदन करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया।

श्री प्रसाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर डीडीसी चुनाव ने अलगाववादियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। एक तरफ पाकिस्तान की ओर से लगातार गोले बरस रहे थे तो दूसरी ओर आतंकवादियों की धमकी। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए जम्मू-कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र में अपना विश्वास दृढ़ करते हुए जिस तरह अपनी भूमिका निभाई, यह वाकई काबिलेतारीफ है। पहली बार जनता ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र में ईमानदार चुनाव को जमीन पर देखा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की एक प्रमुख विशेषता रही कि सैकड़ों नए स्वतंत्र उम्मीदवारों ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इसमें भागीदारी की। कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने खुलकर गुपकार एलायंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यह दिखाता है कि राज्य में नई लीडरशिप उभर रही है और तुष्टिकरण एवं परिवारवाद की राजनीति का अंत हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में आशा भरी नई आवाज का उदय हो रहा है। जम्हूरियत नई अंगड़ाई ले रही है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं। इतिहास में पहली बार बिना किसी भय और डर के यहां की अवाम ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। यह लोकतंत्र की जीत है, जम्मू-कश्मीर के अवाम की जीत है और प्रदेश के विकास में बाधा और रोड़ा अटकाने वालों की हार है। ■

भाजपा हर जगह आ रही है, कांग्रेस जा रही है: प्रकाश जावडेकर

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 13 दिसंबर, 2020 को कहा कि हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा को शानदार सफलता मिली है।

श्री जावडेकर ने कहा कि पहले कोरोना संकट, फिर कोरोना संकट से उपजे वैश्विक आर्थिक संकट, प्रवासी मजदूरों की समस्या और कृषि सुधारों पर विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद देश भर की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन किया है क्योंकि देश की जनता विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को बिलकुल भी पसंद नहीं करती। वे देश की तरक्की देखना चाहते हैं और ये तरक्की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में होंगे, ये उन्हें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के कुशल संयोजन में जिस तरह से बिहार से लेकर देश के अन्य राज्यों में चुनावों का संचालन हुआ है, उसने भाजपा की विजय गाथा को और गति देने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि चाहे असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) का चुनाव हो, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव हों, राजस्थान के स्थानीय निकाय के चुनाव हों, बिहार विधान सभा चुनाव हो, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिस्पल कॉरपोरेशन का चुनाव हो या तेलंगाना से लेकर गुजरात तक और मणिपुर से लेकर कर्नाटक तक उप-चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय हुई है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह आ रही है, कांग्रेस जा रही है। ■

सभी दलों के लोग अटलजी को अपना मानते थे

प्रभात झा

पिछले सात दशक की राजनीति में भारत में एक व्यक्तित्व उभरा और देश ने उसे सहज स्वीकार किया। जिस तरह इतिहास घटता है, रचा नहीं जाता; उसी तरह नेता प्रकृति प्रदत्त प्रसाद होता है, वह बनाया नहीं जाता बल्कि पैदा होता है। प्रकृति की ऐसी ही एक रचना का नाम है पं. अटल बिहारी वाजपेयी।

अटलजी के जीवन पर, विचार पर, कार्यपद्धति पर, विपक्ष के नेता के रूप में, भारत के जननेता के रूप में, विदेश नीति पर, संसदीय जीवन पर, उनकी वक्तृत्व कला पर, उनके कवित्व रूपी व्यक्तित्व पर, उनके रस भरे जीवन पर, उनकी वासंती भाव-भंगिमा पर, जनमानस के मानस पर अमिट छाप, उनके कर्तृत्व पर एक नहीं अनेक लोग शोध कर रहे हैं। आज जो राजनीतिज्ञ देश में हैं, उनमें अगर किसी भी दल के किसी भी नेता से किसी भी समय अगर सामान्य सा सवाल किया जाए कि उन्हें अटलजी कैसे लगते थे? तो सर्वदलीय भाव से एक ही उत्तर आएगा– 'अटलजी हमारे प्रिय नेता थे'!

'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक बार तेरह दिन, दूसरी बार तेरह महीने और तीसरी बार साढ़े चार वर्ष प्रधानमंत्री रहे। अटलजी प्रधानमंत्री बने; यह सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि पूरे भारत की इच्छा थी। वर्षों तक विपक्ष के नेता रहते हुए भारत का अनेक बार भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान अपनी वाणी से प्रत्येक भारतीयों को जहां जोड़ा और भारत को समझा, वहीं सदन के भीतर सत्ता में बैठे लोगों पर मां भारती के प्रहरी बनकर सदैव उनकी गलतियों को देश के सामने रखते रहे। अटलजी के आचरण और वचन में लयबद्धता और एकरूपता थी। वे जब तक सदन में विपक्ष या सत्ता में रहे तब तक सदन के 'राजनैतिक हीरो' अटलजी ही रहे। इस बात को हम नहीं बल्कि तत्कालीन अनेक वरिष्ठ नेतागण स्वयं कहते थे।

'अटलजी' थे तो जनसंघ और आगे भाजपा के, परंतु उन्हें सभी दलों के लोग अपना मानते थे। उनकी ग्राह्यता और स्वीकार्यता तो इसी से पता लग जाती है कि उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता पी. वी. नरसिम्हाराव ने सन् 1994 में प्रतिपक्ष का नेता रहते हुए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भेजा था। जबकि ऐसी बैठकों में भारत का प्रधानमंत्री या अन्य ज्येष्ठ मंत्री ही नेता के रूप में जाते हैं। इस घटना से सारा विश्व चकित था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिराजी हों या स्व. चन्द्रशेखर सभी उन्हें संसद की गरिमा और प्रेरणा मानते हुए सम्मान करते थे।

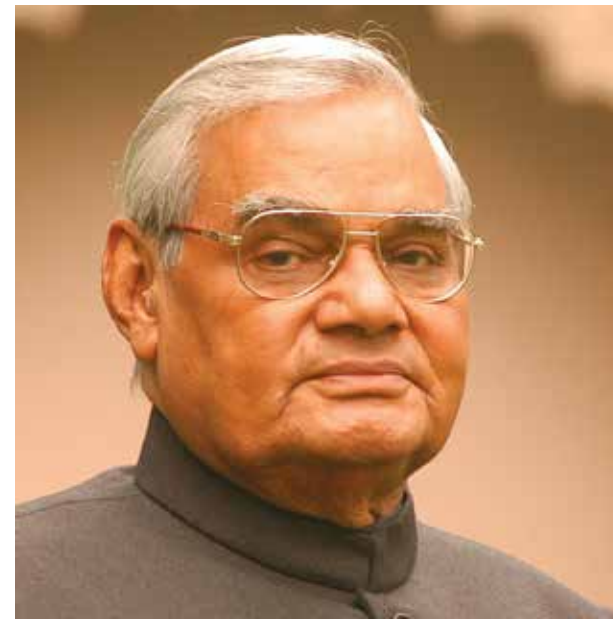

• अटलजी जब जहां और जैसे भी रहे सदैव भारत की मर्यादा और भारतमाता को वैभवशाली बनाने का कार्य किया

भारत के राजनैतिक विश्लेषकों का मानना था कि अटलजी अगर दस वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का भविष्य कुछ और होता। आजादी के दूसरे दिन जो प्राथमिकताएं तय होनी थीं, वह अटलजी के प्रधानमंत्री बनने तक तय नहीं हुई थीं। बावजूद इसके कि अटलजी कवि हृदय और प्रखर पत्रकार रहते हुए अपने कार्यकाल में जो ऐतिहासिक और कठोर निर्णय लिए उसे भारत के राजनैतिक जीवन दर्शन में सदैव याद रखा जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में भाषण

सन 1977 में आपातकाल हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने उन्हें अपने काबीना मे विदेश मंत्री बनाया था। उस दौरान की एक घटना आज भी भारत ही नहीं विश्व भर में लोगों के जहन में ताजा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब विदेश मंत्री के नाते अटलजी पहुंचे और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी में सम्बोधन किया तो पूरा भारत झूम उठा था वे जब जहां और जैसे भी रहे, सदैव भारत की मर्यादा और भारतमाता को वैभवशाली बनाने का कार्य किया।

पोखरण विस्फोट

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि हमें हमारी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इसी के तहत मई 1998 में

भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। वह 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। 11 मई, 1998 यानी आज से 22 साल पहले राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका हुआ और धरती हिल उठी। ये कोई भूकंप नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शौर्य की धमक थी और भारत के परमाणु पराक्रम की गूंज थी। इस परीक्षण से भारत एक मजबूत और ताकतवर देश के रूप में दुनिया के सामने उभरा। दुनिया की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक थीं, लेकिन अब भारत के परमाणु महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था और वह दिन लदने जा रहे थे, जब परमाणु क्लब में बैठे पांच देश अपनी आंखों के इशारे से दुनिया की तकदीर को बदलते थे। पोखरण ने हमें दुनिया के सामने सीना-तानकर चलने की हिम्मत दी, हौसला दिया।

पोटा कानून

13 दिसंबर, 2001 को आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर हमला किया गया। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। आतंरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार ने पोटा क़ानून बनाया। अत्यंत सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था, जिसे 1995 के टाडा क़ानून के मुक़ाबले बेहद कड़ा माना गया था। हालांकि इस क़ानून के बनने के बाद ही इसको लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया कि इसके ज़रिए सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। महज दो साल के अंदर इस क़ानून के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया और क़रीब 4000 लोगों पर मुक़दमा दर्ज किए गए। उस दौरान वाजपेयी सरकार ने 32 संगठनों पर पोटा के तहत पाबंदी लगाई। 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तब ये क़ानून निरस्त कर दिया गया।

लाहौर बस सेवा की शुरुआत

अटलजी हमेशा पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की बात करते थे। उन्होंने पहल करते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में फरवरी, 1999 में दिल्ली-लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। पहली बस सेवा से वे खुद लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। वाजपेयी जी अपनी इस लाहौर यात्रा के दौरान मीनार-ए-पाकिस्तान भी गए। तब तक भारत का कोई भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री मीनार-ए-पाकिस्तान जाने का साहस नहीं जुटा पाए थे। मीनार-ए-पाकिस्तान वो जगह है जहां पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव 23 मार्च, 1940 को पास किया गया था।

स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्रामीण सड़क परियोजना

प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए सड़कों का जाल बिछाने का अहम फैसला लिया था, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना नाम दिया गया। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू किया। जिसका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। आज उन्ही सड़कों के कारण आम आदमी का एक राज्य से दूसरे राज्य जाना आसान हुआ है। बड़े महानगरों के अलावा ग्रामीण इलाकों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। इस योजना के जरिए सभी गांवों में अच्छी सड़क बनी। जिससे वहां यातायात सुगम हुआ और ग्रामीणों को व्यापार के अच्छे अवसर मिले।

अटलजी ने कभी भी 'भारतमाता' को अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। भारत मां के ऐसे महान सपूत और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को भारतरत्न देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सबसे बड़े सम्मान के साथ न्याय किया

दूरसंचार क्रांति

देश में दूरसंचार क्रांति लाने और उसे गांव-गांव तक पहुचाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। वाजपेयी सरकार ने 1999 में बीएसएनएल के एकाधिकार को खत्म कर नई दूरसंचार नीति लागू की। नई नीति के जरिए लोगों को सस्ती कॉल दरें मिली और मोबाइल का चलन बढ़ा। इस फैसले के बाद ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मोबाइल सेवा शुरू की।

8 प्रतिशत से अधिक पहुंची थी आर्थिक वृद्धि दर

अटलजी की सबसे बढ़ी उपलब्धि आर्थिक मोर्चे पर रही। 2004 में जब मनमोहन सिंह ने वाजपेयी सरकार के बाद सत्ता संभाली तब अर्थव्यवस्था की तस्वीर बेहद मजबूत थी। जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक थी, महंगाई दर 4 प्रतिशत से कम थी और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर भरा था।

सर्व शिक्षा अभियान

6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान 'सर्व शिक्षा अभियान' अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। उनके इस क्रांतिकारी अभियान से साक्षरता और शिक्षा दर में अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई। लोगों ने पढ़ाई को महत्व दिया और अपने बच्चों को काम पर भेजने के बजाय पढ़ाई के लिए भेजना आरंभ किया। वाजपेयी सरकार के इस अभियान ने व्यापक सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया।

अटलजी ने कभी भी 'भारतमाता' को अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। भारत मां के ऐसे महान सपूत और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को भारतरत्न देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सबसे बड़े सम्मान के साथ न्याय किया। इसके साथ ही जन-जन में यह विश्वास जगा कि भारत में कर्तृत्व को प्रणाम किया जाता है। इतना ही नहीं दिल्ली में 'सदैव अटल' समाधि बनाकर संपूर्ण राष्ट्र की ओर से जो श्रद्धांजलि दी गई, वह सदैव स्मरणीय रहेगी। ■

(लेखक पूर्व राज्य सभा सांसद हैं)

नई संसद 'आत्मनिर्भर भारत' का बनेगी गवाहः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नया भवन 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आजादी के बाद पहली बार लोगों की संसद बनाने का यह एक शानदार अवसर होगा, जो 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर 'न्यू इंडिया' की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का अवसर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, जो भारतीयता के विचार से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के संसद भवन के निर्माण की शुरुआत हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है।

श्री मोदी ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे साथ मिलकर संसद के इस नए भवन का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि हमारी संसद की इस नई इमारत से कुछ भी अधिक सुंदर या अधिक शुद्ध नहीं हो सकता, जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनायेगा।

प्रधानमंत्री ने उस क्षण को याद किया, जब उन्होंने 2014 में संसद सदस्य के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया था। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार संसद भवन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सिर झुकाया और लोकतंत्र के इस मंदिर को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में कई नई चीजें तैयार की जा रही हैं जो संसद सदस्यों की दक्षता में वृद्धि करेंगी और उनकी कार्य-संस्कृति को आधुनिक बनाएंगी।

श्री मोदी ने कहा कि यदि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी, तो नया भवन देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने का साक्षी बनेगा। यदि पुराने संसद भवन में देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया गया था, तो 21वीं सदी की भारत की आकांक्षाओं को नए भवन में पूरा किया जाएगा।

- **यदि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी, तो नया भवन देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने का साक्षी बनेगा। यदि पुराने संसद भवन में देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया गया था, तो 21वीं सदी की भारत की आकांक्षाओं को नए भवन में पूरा किया जाएगा**

प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य जगहों में लोकतंत्र चुनाव-प्रक्रियाओं, शासन और प्रशासन से जुड़ा है, लेकिन भारत में लोकतंत्र जीवन मूल्यों के बारे में है, यह जीवन की पद्धति है और राष्ट्र

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास किया। यह भवन संसद की उत्पादकता बढ़ाएगा, संस्था को जरूरी उन्नयन व सुविधाएं देगा तथा प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने में क्रांतिकारी सिद्ध होगा।

– जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

की आत्मा है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है। भारत के लोकतंत्र में एक जीवन मंत्र है, जीवन का एक तत्व है और साथ ही व्यवस्था की एक प्रणाली भी है।

श्री मोदी ने कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक ताकत है जो देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है और देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र का हर साल निरंतर नवीनीकरण होता है और यह देखा जाता है कि हर चुनाव के साथ मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र हमेशा से शासन के साथ मतभेदों को हल करने का एक साधन रहा है। विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न दृष्टिकोण एक जीवंत लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा है कि मतभेदों के लिए हमेशा जगह रहती है, क्योंकि यह प्रक्रिया से पूरी तरह से पृथक भी नहीं है।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नीतियां और राजनीति भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए हैं और इस अंतिम लक्ष्य के लिए कोई विभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहसें, संसद के भीतर हों या बाहर, लेकिन इन बहसों में राष्ट्र सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण निरंतर परिलक्षित होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने लोगों से यह याद रखने का आग्रह किया कि लोकतंत्र के प्रति आशावाद को जगाये रखने की जिम्मेदारी लोगों की ही है और यही संसद भवन के अस्तित्व का आधार है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि संसद में प्रवेश करने वाला प्रत्येक सदस्य जनता के साथ-साथ संविधान के प्रति भी उत्तरदायी होता है।

श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर का अभिषेक करने के लिए कोई रीति-रिवाज़ नहीं हैं। लोगों के प्रतिनिधि जो इस मंदिर में आयेंगे, वे ही इसका अभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण, उनकी सेवा, आचरण, विचार और व्यवहार इस मंदिर का जीवन बन जाएगा। भारत की एकता और अखंडता के प्रति उनके प्रयास ऐसी ऊर्जा बन जाएंगे, जो इस मंदिर को जीवन प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि जब प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शिक्षा और अनुभव को यहां पूरी तरह से प्रस्तुत करेगा, तो यह नया संसद भवन पवित्रता प्राप्त करेगा।

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे भारत को सबसे पहले रखने का संकल्प लें, केवल भारत की प्रगति और भारत के विकास की पूजा करें, हर निर्णय देश की ताकत बढ़ाए और देश का हित सर्वोपरि हो। उन्होंने सभी से प्रतिज्ञा लेने को कहा कि उनके लिए राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होगा। देश के लिए उनकी चिंता उनकी अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण होगी। देश की एकता, अखंडता से ज्यादा उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। देश के संविधान की गरिमा को बनाये रखने और आदर्शों को पूरा करना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। ■

नये संसद भवन का शिलान्यास हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, मैं इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं। संसद भवन हमारे लोकतंत्र का आस्था केंद्र है, जो हमें स्वतंत्रता के मूल्य व उसके संघर्ष की याद दिलाता है और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित भी करता है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा जो देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का केंद्र बनेगा। मोदी सरकार देश के गरीब व वंचित वर्ग को सशक्त करने में पूरी निष्ठा व समर्पण से जुटी है और यह नया संसद भवन हमारे इस संकल्प को चरितार्थ करने का साक्षी बनेगा।

– अमित शाह, केन्द्रीय गृहमंत्री

'राजनीति इंतजार कर सकती है, देश का विकास नहीं'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 दिसंबर को कहा कि राजनीति इंतज़ार कर सकती है, सोसायटी इंतज़ार नहीं कर सकती है। देश का विकास इंतज़ार नहीं कर सकता। गरीब, समाज के किसी भी वर्ग का हो, वो इंतज़ार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित, विकास का इंतज़ार नहीं कर सकते।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के शताब्दी समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी बात हमारे युवा, आप सभी, और इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है, सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है।

श्री मोदी ने कहा कि देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक, संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें, सभी अपने सपने पूरे कर पाएं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है वो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं।

• देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक, संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रहे

उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले। बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए। बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। बिना किसी भेदभाव, कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया। बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए, हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट 70 प्रतिशत से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रही है, लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70 परसेंट से ज्यादा मुस्लिम बेटियां, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थीं। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मिशन मोड में अलग से शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70 प्रतिशत से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब-करीब 30 प्रतिशत रह गया है।

श्री मोदी ने कहा कि समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं, जो हम मिल करके हासिल न कर सकें। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन-सहन हो, अवसर हों, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये वो चीज़ें हैं जो हर नागरिक के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर हम अपनी राजनैतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, आप उस ऐतिहासिक समय के भी साक्षी बनेंगे। इतना ही नहीं, इन 27 साल में आधुनिक भारत बनाने के आप हिस्सेदार होंगे। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देशहित सोचना है, आपका हर निर्णय देशहित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है, हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे, हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ■

भारत-बांग्लादेश के बीच हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा समेत हुए सात समझौते

भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध बंधुत्व पर आधारित तथा संप्रभुता, समानता, विश्वास एवं आपसी समझ पर आधारित एक व्यापक साझेदारी का प्रतिबिम्ब है, जो आगे बढ़कर एक रणनीतिक साझेदारी तक जाता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश को 'पड़ोसी प्रथम' नीति का प्रमुख स्तम्भ बताते हुए 17 दिसंबर को कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना उनकी विशेष प्राथमिकता रही है तथा कोविड-19 के कठिन समय में दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है।

श्री मोदी ने बांग्लोदश की समकक्ष श्रीमती शेख हसीना के साथ ऑनलाइन शिखर वार्ता में यह बात कही। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते सहयोग के अनुरूप भारत और बांग्लादेश ने हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इसके साथ ही सीमापार चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल सम्पर्क को बहाल किया गया, जो 1965 तक परिचालन में था।

चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल सम्पर्क को बहाल करने से असम और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लिये सम्पर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच 1965 तक मुख्य ब्राडगेज सम्पर्क का एक हिस्सा था। श्री मोदी और श्रीमती हसीना ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी 'पड़ोसी प्रथम' नीति का एक प्रमुख स्तम्भ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन संतोष की बात है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा।

श्री मोदी ने कहा कि चाहे वो दवाइयों या चिकित्सा उपकरण या फिर चिकित्सा पेशेवरों का एक साथ काम करने का विषय हो, हमारा सहयोग अच्छा रहा है। टीका के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। वहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने कहा कि भारत एक सच्चा दोस्त है।

श्रीमती हसीना ने कहा कि मैं भारत के कोविड-19 से निपटने के तरीके की सराहना करना चाहती हूं, उम्मीद है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भूमि सीमा कारोबार में बाधाओं को हमने कम किया। दोनों देशों के बीच सम्पर्क का विस्तार किया गया तथा नए साधनों को जोड़ा गया। यह सब हमारे संबंधों को और मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है।

श्री मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपके साथ बंगबंधु के सम्मान में एक डाक टिकट का विमोचन और बापू और बंगबंधु के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी, इसमें विशेष खंड को कस्तूरबा गांधी जी और पूजनीय बंगमाता जी को भी समर्पित किया गया है। ■

बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी तक जाता है: संयुक्त वक्तव्य

भारत-बांग्लादेश आभासी शिखर बैठक पर जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच की साझेदारी को परिभाषित करने वाले इतिहास, संस्कृति, भाषा एवं अन्य अनोखी समानताओं के साझे बंधनों पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध बंधुत्व पर आधारित तथा संप्रभुता, समानता, विश्वास एवं आपसी समझ पर आधारित एक व्यापक साझेदारी का प्रतिबिम्ब है, जो आगे बढ़कर एक रणनीतिक साझेदारी तक जाता है।

उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों, मुक्तियोद्धाओं और भारतीय सैनिकों को उनके महान बलिदानों के लिए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दो मित्र देशों के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप लोकतंत्र और समानता के पोषित मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का प्रण लिया। ■

किसानों को अन्नदाता के रूप में देखती है हमारी सरकार: नरेन्द्र मोदी

भारतीय किसानों की विकसित देशों में किसानों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए, जिसमें अब ज्यादा देरी नहीं की जा सकती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम मध्य प्रदेश में हुए किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने शीत गृह अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि किसान चाहे कितनी भी कठिन मेहनत कर लें, अगर फल-सब्जियों-अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था न हो तो किसानों को भारी नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

उन्होंने उद्योग जगत से आधुनिक भंडार सुविधाएं, शीत गृह के विकास और नए खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों की स्थापना में योगदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यही किसानों की सेवा होगी और वास्तव में यह देश की सेवा भी होगी।

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय किसानों की विकसित देशों में किसानों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए, जिसमें अब ज्यादा देरी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत में मौजूदा हालात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुविधाओं और आधुनिक विधियों की कमी के कारण किसान असहाय हो जाते है, जिसमें पहले ही काफी विलंब हो चुका है।

कृषि कानूनों पर हाल में हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि इन कृषि कानूनों पर पिछले 20-22 वर्षों से परामर्श चल रहा है और ये कानून रातोंरात नहीं आ गए। उन्होंने कहा कि देश के किसान, किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे देश के प्रगतिशील किसान लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि दलों के घोषणा पत्रों में उल्लेख होने के बाद भी इन सुधारों को ईमानदारी से नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब लागू हुए कृषि सुधार पूर्व में हुई चर्चा से अलग नहीं थे।

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली सरकारों ने 8 वर्ष तक स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। यहां तक कि किसानों के आंदोलन से भी इन लोगों की नींद नहीं टूटी थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि उनकी सरकार का किसान पर ज्यादा खर्च न हो।

उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीति के लिए उनके द्वारा किसानों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि उनकी सरकार किसानों के लिए समर्पित है और किसानों को अन्नदाता के रूप में देखती है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को इस सरकार द्वारा लागू किया गया, किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है।

कर्ज माफी पर श्री मोदी ने कहा कि इसका लाभ छोटे किसान तक नहीं पहुंच पाता, जो बैंक नहीं जाते हैं और जो कर्ज नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना से किसानों को हर साल लगभग 75 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे, जो सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। किसी तरह की चोरी नहीं होगी, कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने नीम कोटिंग और भ्रष्टाचार पर वार के चलते यूरिया की उपलब्धता बढ़ने के बारे में भी विस्तार से बताया।

श्री मोदी ने इस बात की आलोचना की कि यदि पिछली सरकारों को किसानों की चिंता होती, तो देश की लगभग 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक अटकी नहीं रहतीं। अब हमारी सरकार इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन के रूप में पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर खेत तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अनाज उत्पादक किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन को समान रूप से प्रोत्साहन दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए नीली क्रांति योजना को लागू किया गया है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का भी शुभारम्भ किया गया था। इन प्रयासों के चलते देश में मछली उत्पादन के सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हाल में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अविश्वास की कोई वजह नहीं है और झूठ के लिए यहां कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने लोगों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा कि यदि सरकार का इरादा एमएसपी हटाने का था, तो वह स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट क्यों लागू करती।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी एमएसपी पर सामान्य रूप से ही खरीद हुई थी। श्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी व्यवस्था पहले ही तरह ही लागू रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने न सिर्फ एमएसपी बढ़ाया है, बल्कि एमएसपी पर ज्यादा खरीद भी की है।

श्री मोदी ने उस दौर को याद दिलाया, जब देश को एक दाल संकट का सामना करना पड़ा था। देश में शोरशराबे के बीच विदेश से दालों का आयात किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 2014 में नीति में बदलाव किया और किसानों से एमएसपी पर 112 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की, जबकि 2014 से पहले 5 साल के दौरान महज 1.5 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। आज, दाल किसानों को ज्यादा धनराशि मिल रही है, इसके साथ ही दालों की कीमतों में भी कमी आई है और इसका फायदा सीधे गरीबों को मिला है।

श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नए कानून से किसानों को मंडियों या उनके बाहर बिक्री की स्वतंत्रता मिली है। किसान अपनी उपज वहां बेच सकता है, जहां उसे ज्यादा लाभ मिले। नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार एपीएमसी के आधुनिकीकरण पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रही है।

अनुबंधित कृषि पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह हमारे देश में वर्षों से लागू है। उन्होंने कहा कि अनुबंधित कृषि में सिर्फ फसलों या उपज का लेन-देन होता है, लेकिन जमीन किसान के पास ही बनी रहती है। समझौते से जमीन का कोई मतलब नहीं है। यदि प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान को पूरा पैसा मिलता है। नए कानून ने किसान के लिए अप्रत्याशित लाभ का एक हिस्सा सुनिश्चित किया है।

उन्होंने एक बार फिर से ऐसे किसानों की चिंताओं के समाधान का भरोसा दिलाया, जिन्हें इन प्रयासों के बाद भी आशंकाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक बार फिर 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर विस्तार से इस विषय पर बात करेंगे। इसी दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। ■

जल जीवन मिशन के तहत 278 लाख परिवारों को मिला नल जल कनेक्शन

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की 16 दिसंबर, 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत 278 लाख घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। 15 अगस्त, 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। फिलहाल देश के 6.01 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से अपने घरों में पीने योग्य पानी मिल रहा है। देशभर में 18 जिलों ने सभी घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं और हर घर में नल का जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

जल शक्ति मंत्रालय देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध

- **देश के 6.01 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से अपने घरों में पीने योग्य पानी मिल रहा है। देशभर में 18 जिलों ने सभी घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं**

कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन को 2024 तक लागू करने में जुटा है।

मिशन के अस्तित्व में आने के बाद राज्यों से आधारभूत डेटा के पुनर्मूल्यांकन कार्य का अनुरोध किया गया था, उसके अनुसार देश में 19.05 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 3.23 करोड़ परिवारों को पहले ही नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। शेष 15.81 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन दिए जाने हैं। इस प्रकार पहले से ही दिए गए कनेक्शनों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से लगभग 16 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 3.2 करोड़ परिवारों को कवर किया जाना है, यानी दैनिक आधार पर 88,000 नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 23,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग का 50 प्रतिशत अनुदान यानी 30,375 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिसका उपयोग जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए किया जाएगा। इससे गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में मदद मिलेगी, ताकि लोगों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी मिलता रहे। ■

कृषि सुधारों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है: नरेंद्र सिंह तोमर

किसानों के हितों में किए गए कृषि सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 दिसंबर, 2020 को किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में श्री तोमर ने लिखा कि ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों में मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इससे बहुत खुश हैं, किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं, जिन्होंने नए कृषि कानून का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। श्री तोमर ने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी।

आठ पन्ने के पत्र में श्री तोमर ने कहा है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले छह वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। पिछले छह साल में हमारी सरकार ने किसानों का मुनाफा बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनका फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है।

श्री तोमर ने लिखा कि मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए, समझते हुए, मैं बड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी।

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और सिरे से खारिज करें। श्री तोमर ने कहा कि किसान सतर्क रहें, इस आंदोलन में ऐसे लोग घुस गए हैं जिनका मकसद किसानों का हित नहीं है। बीते 6 सालों से एक ही गुट कभी दलितों को भड़काकर कभी दूसरी जातियों को भड़काकर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ट्वीटर हैंडल पर पत्र को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह! 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास

झूठ	सच
MSP की व्यवस्था खत्म हो रही है। APMC मंडियां बंद की जा रही हैं।	MSP सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। APMC मंडियां कायम रहेंगी। APMC मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं।
किसानों की जमीन खतरे में है।	एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा।
किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन हथिया सकते हैं।	परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है।	फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा।
किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा।	किसानों का भुगतान तय समयसीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा।
किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं।	किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं।
पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है।	कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक हैं।
इन कानूनों को लेकर कोई सलाह-मशविरा या चर्चा नहीं की गई है।	दो दशकों तक विचार-विमर्श हुआ है। साल 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल APMC एक्ट; 2007 के APMC Rules; 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति; 2017 का मॉडल APLM एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी।

किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है।

उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिये, किसानों के हितों में किये गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री तोमर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई-बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।

श्री तोमर के पत्र पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि किसानों की व्यथा को समझने वाले तथा उनके निवारण के लिए संकल्पित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनेक कृषि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अन्नदाता भाई-बहनों के जीवन को सुगम बनाया है, अधिकारों को सशक्त किया है एवं अपार संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्र के माध्यम से किसान भाई-बहनों में फैलाए जा रहे अफ़वाहों के निवारण व कृषि आय को दोगुना करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया है। मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे इस पत्र को सभी अन्नदाता भाई-बहनों तक पहुंचाएं।

श्री तोमर के पत्र के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जितने काम 6 दशकों तक नहीं हुए, उससे अधिक नरेन्द्र मोदी ने 6 वर्षों में किये हैं। कृषि सुधारों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी का यह पत्र मोदी सरकार की किसानों के हितों के प्रति समर्पण और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेन्द्र मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ■

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 23 दिसंबर को अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 'अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)' की केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की, ताकि वे अपनी उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत) खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा 'प्रतिबद्ध देयता' प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी।

इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11वीं से शुरू होने वाले मैट्रिक के बाद के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिली है। इस योजना में सरकार शिक्षा की लागत का वहन करती है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित जातियों का जीईआर (उच्चतर शिक्षा) राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। यह योजना गरीब-से-गरीब छात्रों को नामित करने, समय पर भुगतान करने, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता पर जोर देती है। विवरण निम्नानुसार है:

1. गरीब-से-गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।
2. यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता, तथा बिना विलम्ब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी।
3. राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे।
4. इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से और अधिमान्यता आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश (60 प्रतिशत) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम में सीधे जारी किया जाएगा।
5. निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्ध-वार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा।

केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। ■

लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए अधिक उपयुक्त है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 दिसंबर को भारत–जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध के संदेशों का प्रकाश भारत से दुनिया के अनेक हिस्सों तक फैला है। यह प्रकाश एक स्थान पर स्थिर नहीं रहा है। जिस नये स्थान पर यह प्रकाश पहुंचा है वहां भी बौद्ध धर्म के विचारों ने सदियों से आगे बढ़ना जारी रखा। यहां प्रस्तुत है श्री मोदी के संबोधन का संपादित पाठ:

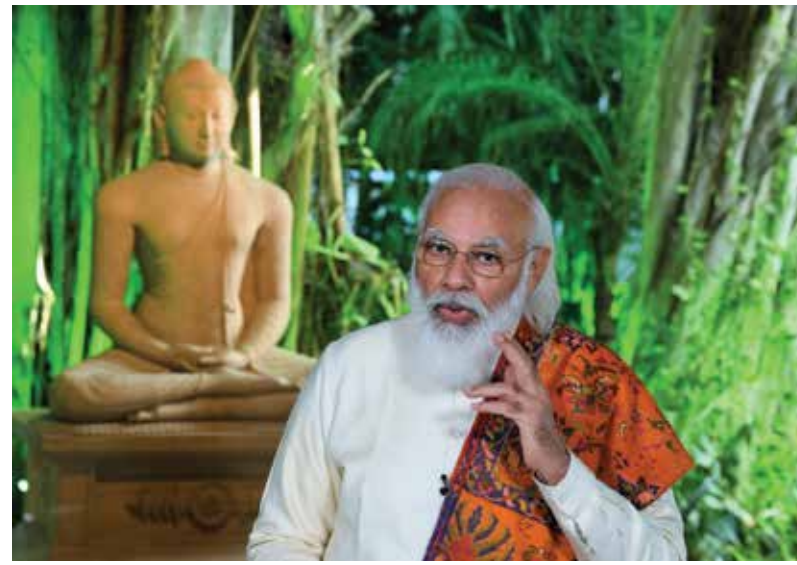

छठे भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। हमने पांच साल पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के साथ सम्मेलनों की यह शृंखला शुरू की थी। तब से संवाद की यह यात्रा नई दिल्ली से टोक्यो, यंगून से उलानबटार तक होकर गुजरी है। यह यात्रा वार्ता और बहस को प्रोत्साहन देने, लोकतंत्र, मानवतावाद, अहिंसा, स्वतंत्रता और सहिष्णुता के साझा मूल्यों पर प्रकाश डालने और आध्यात्मिक तथा विद्वत्तापूर्ण आदान-प्रदान की हमारी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने के अपने मूल उद्देश्यों के लिए हमेशा उचित रही है। मैं 'संवाद' को निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए जापान सरकार को धन्यवाद देता हूं।

इस मंच ने विशेष रूप से युवाओं में भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा काम किया है। ऐतिहासिक रूप से गौतम बुद्ध के संदेशों का प्रकाश भारत से दुनिया के अनेक हिस्सों तक फैला है। यह प्रकाश एक स्थान पर स्थिर नहीं रहा है। जिस नये स्थान पर यह प्रकाश पहुंचा है वहां भी बौद्ध धर्म के विचारों ने सदियों से आगे बढ़ना जारी रखा है। इस कारण बौद्ध धर्म के साहित्य और दर्शन का यह बहुमूल्य खजाना अलग-अलग देशों और भाषाओं में अनेक मठों में पाया जाता है।

- **समाज जो खुले दिमाग वाला लोकतांत्रिक और पारदर्शी है वही नवाचार के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए प्रगतिरूपी प्रतिमान को बदलने का अब पहले की अपेक्षा बेहतर समय है। वैश्विक विकास की चर्चा कुछ लोगों के बीच ही नहीं की जा सकती है। इसके लिए दायरे का बड़ा होना जरूरी है**

लेखन पूरी मानवता का खजाना होता है। मैं आज ऐसे सभी पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों के लिए पुस्तकालयों के सृजन का प्रस्ताव करना चाहता हूं। हम भारत में इस तरह की सुविधा का निर्माण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और इसके लिए उचित संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। यह पुस्तकालय विभिन्न देशों से इस प्रकार के बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियों का संग्रह करेगा। इसका उद्देश्य ऐसे साहित्य का अनुवाद करना और इसे बौद्ध धर्म के सभी भिक्षुओं और विद्वानों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है। यह पुस्तकालय ऐसे साहित्य का भंडार मात्र ही नहीं होगा।

यह शोध और संवाद के लिए एक मंच तथा मनुष्यों के बीच, समाज के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सच्चा 'संवाद' भी होगा। इसके शोध में यह जांच करना भी शामिल होगा कि बुद्ध के संदेश किस प्रकार समकालीन चुनौतियों के मुकाबले हमारे आधुनिक विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इनमें गरीबी, जातिवाद, उग्रवाद, लिंग भेदभाव, जलवायु परिवर्तन और ऐसी कई अन्य चुनौतियां शामिल हैं।

लगभग तीन सप्ताह पहले मैं सारनाथ गया था। सारनाथ वह जगह है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ से प्रकट हुआ यह ज्योति पुंज पूरी दुनिया में फैल गया और इसने करुणा, महानता और सबसे बढ़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए मानव कल्याण को गले लगाया।

इसने धीरे-धीरे शांतिपूवर्क विश्व इतिहास के मार्ग को ही परिवर्तित कर दिया।

सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने धम्म के अपने आदर्श के बारे में विस्तार से उपदेश दिया था। धम्म के केन्द्र में मानव और अन्य मनुष्यों के साथ उनका संबंध स्थित हैं। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक शक्ति होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। संवाद ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस ग्रह में सकारात्मकता, एकता और करुणा की भावना का प्रसार करे और वह भी ऐसे समय में जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

यह नए दशक का पहला संवाद है। यह मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में आयोजित किया जा रहा है। आज किये जाने वाले हमारे कार्य हमारे आने वाले समय का आकार और रास्ता तय करेंगे। यह दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा, जो सीखने और साथ-साथ नव परिवर्तन करने पर उचित ध्यान देंगे। यह उज्ज्वल युवा मस्तिष्कों को पोषित करने के बारे में भी है, जिससे आने वाले समय में मानवता के मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे नवाचार को आगे बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर नवाचार मानव सशक्तिकरण का मुख्य आधार है।

समाज जो खुले दिमाग वाला लोकतांत्रिक और पारदर्शी है वही नवाचार के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए प्रगतिरूपी प्रतिमान को बदलने का अब पहले की अपेक्षा बेहतर समय है। वैश्विक विकास की चर्चा कुछ लोगों के बीच ही नहीं की जा सकती है। इसके लिए दायरे का बड़ा होना जरूरी है। इसके लिए कार्य सूची भी व्यापक होनी चाहिए। प्रगति के स्वरूप को मानव केन्द्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए और वह हमारे परिवेश के अनुरूप होना चाहिए।

यमक वग्गो धम्मपदः में उचित रूप से वर्णन किया गया हैः

न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचं।
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो॥

शत्रुता से कभी शांति हासिल नहीं होगी। विगत में मानवता ने सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया। साम्राज्यवाद से लेकर विश्व युद्ध तक, हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक, हमने संवाद किए लेकिन उनका उद्देश्य दूसरों को नीचे खींचना था। आइये, अब हम मिलकर ऊपर उठें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें शत्रुता को सशक्तता में बदलने की शक्ति मिलती है। उनकी शिक्षाएं हमें बड़ा दिलवाला बनाती हैं। वे हमें विगत से सीखने और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम करने की शिक्षा देती हैं। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अच्छी सेवा है।

'संवाद' का सार घनिष्ठता बनाए रखना है। 'संवाद' हमारे अंदर बेहतर समावेश करे, यह हमारे प्राचीन मूल्यों को आकर्षित करने और आने वाले समय के लिए अपने आपको तैयार करने का समय है। हमें मानवतावाद को अपनी नीतियों के केन्द्र में रखना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व के केंद्रीय स्तंभ के रूप में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व स्थापित करना चाहिए। स्वयं अपने साथ, अपने अन्य साथियों और प्रकृति के साथ 'संवाद' इस पथ पर हमारा मार्ग प्रकाशित कर सकता है। ■

प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को मिली औपचारिक मान्यता

केंद्रीय आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 17 दिसंबर को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की। केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद नाइक और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नाइक ने योगासन प्रतियोगिताओं को भारतीय योग परंपरा का हिस्सा बताया, जहां सदियों से ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी कई स्तरों पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं को राष्ट्रीय पटल पर उभरने के लिए मजबूत और दीर्घकालिक स्वरूप का सामने आना बाकी है।

श्री नाइक ने कहा कि योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने का सरकार का फैसला योग क्षेत्र के हितधारकों के साथ

3-4 साल के व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि योगासन योग का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, जो सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति है और फिटेनस व सामान्य स्वास्थ्य में अपनी प्रभावकारिता के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिला अमेरिका का 'लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार

अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक 'लीजन ऑफ मेरिट' (Legion of Merit) दिया। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह सम्मान दिया गया। भारत की ओर से राजदूत तरनजीत सिंह संधु ने ह्वाइट हाउस में अमेरिका के नैशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर रॉबर्ट ओ ब्रायन से सम्मान स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 दिसंबर को अमेरिका से लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार ग्रहण करने पर कहा कि यह पुरस्कार भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर बढ़ती सहमति की मान्यता है। श्री मोदी ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किए गए 'लीजन ऑफ मेरिट' पुरस्कार से अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किए गए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से स्वयं को अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में भारत और अमेरिकी लोगों के प्रयासों को मान्यता देता है और दोनों देशों के बीच भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी के संदर्भ में द्विदलीय सहमति में परिलक्षित होता है।

श्री मोदी ने कहा कि 21वीं शताब्दी में अप्रत्याशित चुनौतियां और अवसर भी हैं। भारत-अमेरिका संबंध अपने लोगों की

विशिष्ट दृढ़ता की व्यापक क्षमता का लाभ संपूर्ण मानवता के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत के 1.3 बिलियन लोगों की ओर से भारत-अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार और दोनों देशों के अन्य सभी हितधारकों के साथ कार्य जारी रखने के अपनी सरकार के दृढ़विश्वास और प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। ■

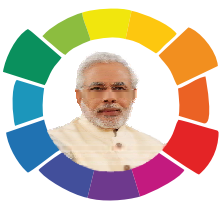

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

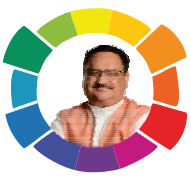

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब (नई दिल्ली) में गुरु तेगबहादुर को नमन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मध्य प्रदेश में संपन्न हुए किसान सम्मेलन को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कच्छ (गुजरात) में विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संसद परिसर (नई दिल्ली) में 2001 में संसद पर हुए हमले के शहीदों को नमन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

छायाकार: अजय कुमार सिंह